(b) if so, what decision Government have taken in this respect?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE (KUMARI SELJA): (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India have already accepted the recommendations of the Hakar Committee regarding the restructuring of the Lalit Kala Akademi.

**Female infarnticide in the country**

562. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there has been an alarming rise in female infanticide in various parts of the country;

(b) if so, what are the details of such cases in 1992, state-wise; and

(c) what steps Government are taking to curb this evil practice?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI) (a) and (b) The information is not centrally maintained.

(c) The offences relating to female infanticide are dealt with under the existing provisions of the Indian Penal Code. Various programmes of action and advocacy are also implemented to project a positive image of girl children so as to bring about changes in societal attitudes towards them. A National Plan of Action for the SAARC Decade (1991-2000) of the Girl Child focussing on survival, protection and development of the girl child has been formulated. A special set of interventions for adolescent girls has been institutionalised through the ICDS infrastructure.

**National Literacy Programme**

563. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the national literacy programme has suffered a setback in 1992 and is in disarray;

(b) whether the National Literacy Mission is now headless; and

(c) what steps Government propose to take to renew interest in the programme?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a): No, Sir. During 1992-93 Total Literacy Campaign were approved in 56 districts and Post Literacy Campaign in 32 districts.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

**वित्तीय संकट का सामना कर रही शैक्षणिक संस्थायें**

564. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिक्षा/उच्च शिक्षा को प्राथमिकता /बढ़ावा देने का कार्यक्रम वित्तीय संकट के कारण ठप्प पड़ गया है ;

(ख) क्या सरकार शिक्षा के लिये धन जुटाने हेतु किसी कोष की स्थापना करने का विचार रखती है ;

(ग) इस समय देश में ऐसे विश्व विद्यालयों की राज्यवार और विश्वविद्यालय वार संख्या कितनी है जिन्हें बजट घाटा हो रहा है ;

(घ) क्या संसाधनों के अभाव में स्कूलों/कालेजों में बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है और क्या सरकार इस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करेगी ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :**

(क) जी, नहीं।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किये जाते हैं और उनका सम्पूर्ण अनुरक्षण तथा विकास व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है । राज्य विश्वविद्यालय राज्य विधान-मंडलों के अधिनियमों द्वारा स्थापित किये जाते है और उनका अनुरक्षण व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य सरकारों को केवल उनके योजनागत कार्यक्रमों तथा वह भी उनकी आवश्यकताओं के एक भाग के रूप में वित्तीय-सहायता प्रदान करता है । मुख्य रूप से राज्य सरकारों का यह उत्तरदायित्व है कि वे उनके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों को उचित योजनागत अनुदान प्रदान करें । योजनागत और योजनेत्तर के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों के वित्तीय घाटे के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई सूचना नहीं रखी जाती है । जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदानों में घाटे का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) स्कूल/कालेज सामान्यतया राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों या निजी प्रबन्धों/न्यासों द्वारा स्थापित किये जाते हैं और विश्वविद्यालय संसद और राज्य विधान मंडलों के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं । इन संस्थाओं में निर्धारित स्तर की मूलभूत सुविधाओं तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्यतया उस एजेंसी की है, जो संबंधित संस्था को स्थापित करती है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

**फतेहपुर सीकरी की ऐतिहासिक इमारतों को खतरा**

565. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि फतेहपुर सीकरी में बारूद से किए जा रहे विस्फोटों से उस क्षेत्र का कुछ ऐतिहासिक इमारतों के लिए भारी खतरा उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस क्षेत्र की ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :**

(क) और (ख) फतेहपुर सीकरी के संरक्षित पुरातत्वीय क्षेत्र के बाहर खान की खुदाई का कार्य राज्य सरकार की विशेष अनुमति से किया गया है । डायनामाइट का प्रयोग मनाही है । तो भी, इक्के-दुक्के उदाहरण हैं डायनामाइट का प्रयोग अनधिकृत रूप से किया गया है । जब ऐसा होता है, तब स्थानीय प्राधिकारियों से कहा जाता है कि वे ऐसा अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही करें, ताकि आसपास के स्मारकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके ।